Assistance to Gujarat for National Highways

2576. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance given to the Gujarat Government from the Central Road Funds during the last three years;

(b) the names of the National Highways for which the above assistance was given; and

(c) the names of the projects that are likely to be undertaken in Gujarat during 1992-93 and the financial provision likely *to* be made therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI IAGDISH TYTLER) : (a) Funds released to Government of Gujarat for State Road projects from the Central Road Fund during the last three years are as under :

Year	Amount (Rs in lakhs)
1989-90	100.00
1990-91	150.00
1991-92	60.00

(b) Since augmentation of Central Road Fund as per Revised Resolution adopted by the Parliament on 13-5-1988 which provides for 351 percent of accruals to the Fund to be utilised by the Central Government for development and maintenance of National' Highways has not yet taken place, no amount has been allocated from Central Road Fund for National Highways so far.

(c) New proposals to be undertaken in Gujarat during 1992-93 and financial provision; likely to be made therefor,. would depend *inter-alia* on actual augmentation of Central Road Fund, free-balatice available for Gujarat, proposals recommended by the State Government and schemes approved.

12—419RSS/93

गुजरात में पुलों का निर्माण एवं मरम्मत

2577. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल निर्मित करने का विचार है,

(ख) उस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी मरम्मतों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गुजरात राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर, दिनांक 1-4-92 तक, 69 पुलों को स्वीकृति दी गई थी। 1–4–92 तक इनमें से 64 पुल निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में थे। शेष 5 पुलों के निर्माण कार्य को वर्ष 1992–93 में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो पुलों की मरम्मत की जा रही है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में पुलों की मरम्मत पर 162.13 लाख रु० व्यय हुए हैं।

Modernisation of Ship Kepsirs Facilities at Rajabagan Docks in Calcutta

2578. SHRI SURESH KAlMADI : Will the. Minister of -SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether .Government..:have .decided t*o* modernise the ship repair facilities at Rajabagan docks m'Calcutta; and

(b) if so, the estimated expenditure involved therein and the 'likely increase in ship repair capacity as a result thereof?

THE.MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLBR) : (a) Yes Sir.

(b) The estimated expenditure involved therein is Rs. 71.34 crores and the likely capacity for ship repair after modernisation will be 106 vessels per year.

Involvement of Private Sector and Foreign Collaboration in Ship Building

2579. SHRI V. NARAYANASAMY : WiU the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to involve private sector and foreign collaborators in the ship building industry; and

(b) if so, what is the response from the foreign companies thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISK TYTLER) : (a) According to the new Industrial Policy announced by the Government in July, 1991, Shipbuilding Industry has been delicensed except for construction of war ships which has been reserved for the public sector. Further, mechanised sailing vessels upto 10.000 DWT have been allowed automatic approval for foreign technology and foreign equity participation upto 51% as per the laid down procedure. Entrepreneurs in the private sector can set up new shipyards in the country witl^ foreign collaboration as necessary.

(b) Some, of the foreign companies have shown interest in technical collaboration with the Indian Shipyards.

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा उन्हें जोड़ा जाना

2580. श्री महेश्वर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चण्डीगढ़--मनाली को मण्डी--पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से वाया बाजौरा-कांडी सम्पर्क सड़क के द्वारा तथा चण्डीगढ़-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को शिमला--रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाया जलोड़ी सम्पर्क सड़क के द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां । राज्य सरकारों ने नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए 135 सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कें शामिल हैं और राज्य वार प्रस्तावों का सारांश विवरण रूप में संलग्न है [नीचे देखिए ।]

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित किए जाने हेतु, बाजोरा--कांडी के माध्यम से एन० एच० 20 और एन० एच० 21 को जोड़ने के लिए, एक प्रस्ताव भेजा है । तथापि, संसद द्वारा मई, 1988 में पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि न होने के कारण इस प्रस्ताव को मंजूरी देना संभव नहीं हुआ है । एन० एच० 21 और 22 को वाया जालोरी जोड़ने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।